



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रकाशरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 1975/अग्रहायण 3, 1897

No. 477]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 1975/AGRAHAYANA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th November 1975

S.O. 675(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 726(E), dated the 27th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that (a) the enactments or portions thereof, as the case may be, specified in the Schedule of the said Order shall not apply to the undertaking known as Messrs Ganesh Flour Mills Company Limited (hereinafter referred to as the said undertaking), and (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the said undertaking is a party, or which may be applicable to it immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 26th November, 1973;

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 707(E), IDRA/73, dated the 22nd November, 1973, the duration of the said Order was extended upto the 26th November, 1974;

And whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 673(E)/18FB/IDRA/74, dated the 25th November, 1974, the duration of the said Order was further extended upto the 26th November, 1975;

(2509)

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by another one year commencing from the 27th November, 1975;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby further extends the duration of the said Order upto the 26th November, 1976.

[No. 4/12/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

### उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1975

कां.आ. 675 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां.आ. 726 (ई), तारीख 27 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि (क) उक्त आदेश को अनुसूच में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिनियमवतियाँ या उनके प्रमाण में प्राप्त गणेश पत्रों के अन्तर्गत लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) के नाम से जाना उक्त को लागू नहीं होगा, तथा (ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले प्राप्त सभी ऐश पंक्तिश्री, समाप्ति के हस्तान्तरणपत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंजायों, स्थानों आदेशों या अन्य लिखतों का (जो उनसे भिन्न है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) त्रिनका उक्त उपक्रम एक पक्षकार है या जो उसे लागू हों, प्रवर्तन तथा उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोदूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 26 नवम्बर, 1973 तक विलम्बित रहेंगे; और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. कां.आ. 707 (ई)/आई.डी.आर.ए. 73, तारीख 22 नवम्बर, 1973 द्वारा, उक्त आदेश की कालावधि 26 नवम्बर, 1974 तक बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां.आ. 673 (ई)/18 च ख/आई.डी.आर.ए. 74, तारीख 25 नवम्बर, 1974 द्वारा, उक्त आदेश की कालावधि और बढ़ कर 26 नवम्बर, 1975 तक कर दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 27 नवम्बर, 1975 से प्रारंभ होने वाले एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 26 नवम्बर, 1976 तक और बढ़ा दी है।

[सं. 4/12/72-सं. यू. सी.]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।